



2026:AHC:22622
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या 2192 वर्ष 2026

विपिन कुमार शर्मा
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: कैलाश नाथ सिंह
: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका में मांगी गई एकमात्र राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 तहसीलदार, तहसील सदर, जिला जौनपुर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 26 के अंतर्गत मामले को पंजीकृत करने और इस माननीय न्यायालय द्वारा सिविल विविध रिट याचिका संख्या 38032 वर्ष 2024 [विपिन कुमार शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य] में दिनांक 17.12.2024 को पारित आदेश के अनुसरण में इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्धारित समयावधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

3. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को आदेश से असंतुष्टि है, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

4. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण परिस्थिति है और न ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निचली न्यायालय को उपरोक्त मामले का समयबद्ध तरीके से निर्णय करने का निर्देश देने के लिए कोई तर्क दिया गया है, सिवाय इसके कि मुकदमा वर्ष 2024 में दायर किया गया है।

5. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, अगर न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय विधि के अनुसार चार महीने की अवधि के भीतर किसी भी पक्ष के लिए बिना कोई अनावश्यक स्थगन दिए करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

6. उपरोक्त विचारणियों के साथ, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

2 फरवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"